Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

Original Article

समावेशी विकास :अवधारणा एवं चुनौतियाँ

डॉ.सुरेखा पिपलानी

प्रोफेसर अर्थषास्त्र विभाग, जी.यू.(पी.जी.) कॉलेज बहेड़ी बरेली सम्बद्धः एम.जे.पी. रूहेलखण्ड वि.वि.बरेली

Email: piplanisurekha03@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2025-170906
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 9(A)
Pp.29-32
September 2025
Submitted:22 Aug. 2025
Revised: 3 Sept. 2025
Accepted: 21 Sept. 2025
Published: 30 Sept. 2025

सारांश

समावेशी विकास आज वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चर्चित विषय है। हमारी विकास यात्रा पाषाण काल से प्रारम्भ होकर आज सूचना प्रौद्योगिकी तथा वैश्वीकरण के दौर में पहुँच चुकी है। वर्तमान समय में विकसित एवं अविकसित देशों के मध्य विभाजन रेखा धीरे–धीरे धुंधली होती जा रही है। लेकिन बढ़ती हुई सम्पन्नता के बाद भी समाज का बहुसंख्यक वर्ग आर्थिक असमानता, शोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा गरीबी जैसी विषमताओं के चंगुल में फंसा हुआ है। इन असमानताओं के निदान के लिये समावेशी विकास वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी और लाभ सुनिश्चित किये जाते हैं। यह न केवल आर्थिक विकास पर बल देता है अपितु सामाजिक न्याय, अवसरों की समानता तथा गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता देता है। यह विकास का एक ऐसा मॉडल है जो आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व देता है। इस प्रक्रिया में रोजगार सृजन गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है।

मुख्य शब्दः *समावेशी विकास, असमानता, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक–सुरक्षा*

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से चहुँमुखी विकास कर रही है। विश्व में सर्वाधिक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक तथा विश्व महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हमारा देश आज एक गम्भीर आर्थिक असमानता की तरफ भी बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वेब पोर्टल पर भारत की सफलता का वर्णन इस प्रकार से किया गया है –

'' विश्व का सबसे बड़ा व तेज गति से प्रगति कर रहा लोकतान्त्रिक देश भारत आज एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है।'' लेकिन विकास की वर्तमान अमानवीय एवं संवेदन हीन बाजारवादी व्यवस्था ने हाशिये पर जीवन जी रहे समूहों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है जिससे देश में व्यापक असमानताऐं बनी हुई हैं। इस विकास यात्रा में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाऐं मुख्याधारा के विकास से वंचित हैं। समावेशी विकास का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किये जायें जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

समावेशी विकास की अवधारणाः

समावेशी विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जो व्यापक हो और जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त हो। यह न केवल आर्थिक वृद्धि पर बल देता है बल्कि सामाजिक न्याय, अवसरों की समानता और गरीबी उन्मूलन जैसे पहलुओं को भी प्रमुखता देता है अर्थात विकास का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुँचे और समाज का कोई भी वर्ग विकास प्रक्रिया से अछूता न रहे।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ. सुरेखा पिपलानी, प्रोफेसर अर्थषास्त्र विभाग, जी.यू.(पी.जी.) कॉलेज बहेड़ी बरेली सम्बद्धः एम.जे.पी. रूहेलखण्ड वि.वि.बरेली

How to cite this article:
पिपलानी, . सुरेखा . (2025). समावेशी विकास: अवधारणा एवं चुनौतियाँ. Journal of Research and Development, 17(9(A)), 29–32. https://doi.org/10.5281/zenodo.17492216

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.17492216
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया था कि'' एक विकास प्रक्रिया जो व्यापक—आधारित लाभ देती है और सभी के लिये अवसर की समानता सुनिश्चित करती है।'' समावेशी विकास की अवधारणा का मूल उद्देश्य गरीबी में कमी, मानव विकास, स्वास्थ्य व काम करने और रचनात्मक होने का अवसर देना है। इस अवधारणा में चार विशेषताऐं परिलक्षित होती हैं— अवसर, क्षमता, पहुँच और सुरक्षा। प्रथमत: व्यक्तियों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी आय बढ़ाने पर ध्यान संकेन्द्रित किया जाता है तत्पश्चात उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिये लोगों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये साधन प्रदान करने पर बल दिया जाता है। अवसरों एवं क्षमताओं को एक साथ लाने के लिये साधनों की पहुँच सुगम बनायी जाती है तथा लोगों को आजीविका की अस्थायी अथवा स्थायी हानि से बचाने के लिये साधन उपलब्ध कराकर सुरक्षा दी जाती है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि समावेशी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में लगातार विस्तार से मापा गया आर्थिक विकास समस्त चार आयामों के पैमाने तथा क्षेत्र के विस्तार में सहयोग देता है।

समावेशी विकास के प्रमुख आयाम:

आर्थिक आयाम

समावेशी विकास का आर्थिक पहलू अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। इसके लिये रोजगार सृजन, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन जैसे कदम उठाये जाते हैं। वित्तीय समावेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाऐं समाज के हर वर्ग तक पहुँचे जिससे छोटे—छोटे उद्यमियों और किसानों को भी वित्तीय सहायता मिल सके और वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकें।

सामाजिक आयाम

सामाजिक समावेशन समावेशी विकास का एक अभिन्न अंग है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने पर बल दिया जाता है। भारत में जहाँ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव की समस्या रही है वहाँ सामाजिक समावेशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है।

समावेशी विकास की आवश्यकता:

समावेशी विकास न केवल आर्थिक विकास है बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक अनिवार्यता भी है। समावेशी विकास के अभाव में कोई भी देश अपना विकास सही प्रकार से नहीं कर सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समावेशी विकास की आवश्यकता कई कारणों से और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे देश में जहाँ एक तरफ तीव्र आर्थिक विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ असमानताऐं भी बढ़ रही हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अन्तर, आय की असमानता और सामाजिक भेद—भाव जैसी समस्यायें अभी भी विद्यमान हैं। समावेशी विकास की महत्ता को निम्न लिखित सन्दर्भों में समझा जा सकता है:

- भारत में आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जाने वाला सार्वजनिक व्यय काफी कम है। शिक्षा तक सभी की पहुँच, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ—साथ सार्वभौमिक सस्ती स्वास्थ्य सेवाऐं तथा स्वच्छता एवं पोषण हेतु समावेशी विकास की अत्यन्त आवश्यकता है । एन०एफ०एच०एस०—५ रिपोर्ट के अनुसार भारत में समस्त जनसंख्या समूहों में रक्त अल्पता बढ़ती जा रही है, जिसमें ५ वर्ष से कम आयु के बच्चे, किशोर लड़कियाँ और लड़के तथा गर्भवती महिलाऐं शामिल हैं। हर दूसरी महिला व हर तीन में से दो बच्चे(६—५९महीने) रक्त की कमी से ग्रस्त हैं।
- एक समान समावेशी विकास न हो पाने के कारण देश के विभिन्न भागों में विषमता में वृद्धि होती है जिससे वंचित वर्ग विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते। देश में विभिन्न जातियों, धर्मों तथा आर्थिक वर्गों के लोग रहते हैं जिनके जीवन स्तर और विकास के स्तरों में बहुत विभिन्नताऐं है। विकास के समावेशी न हो पाने के कारण आय वितरण में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण देश के विभिन्न भागों में विषमताओं में वृद्धि होती है। आय वितरण की असमानताओं में पिछले कुछ दशकों में तीव्र वृद्धि हुई है, अत: बढ़ती हुई असमानताओं को दूर करने तथा समानता को बढ़ावा देने के लिये समावेशी विकास की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।
- समावेशी विकास के लिये वित्तीय समावेशन अत्यन्त आवश्यक है। वित्तीय समावेशन कम खर्च में वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास को समावेशी बनाने के लिये देश में सभी वर्गों की बैंकिग सेवाओं तक पहुँच एवं उन्हें सस्ती ऋण सुविधाऐं तथा बीमा और पेंशन योजनाएँ उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

- कमजोर वर्गों को विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाएँ जैसे मनरेगा, जन–धन योजना तथा वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है।
- विकास की ऊँची दर के बाद भी देश के कई क्षेत्र अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं इसलिये आर्थिक विकास को समावेशी विकास बनाने के लिये विकास की रणनीतियों में बुनियादी सुविधाऐं उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है। शहरी और ग्रमीण भारत के बीच की खाई को पाटने के लिये भारत की आधारभूत संरचना का विकास आवश्यक है, इससे लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ आर्थिक उन्नति के अवसर भी मिल सकेंगे। पिछड़े इलाकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गॉवों और शहरों के बीच की दूरी को पाटने की दिशा में ठोस प्रयास है। गांवों को शहरों से जोड़ने की सुविधा अच्छी होने से कृषि से होने वाली आय में भी वृद्धि होती है। इससे गाँव के लेागों के लिये बाजार की पहँच ज्यादा सुगम हो जाती है तथा रोजगार एवं सामाजिक सेवाओं के नये अवसर भी प्राप्त होने लगते हैं।

समावेशी विकास की चुनौतियाँ

समावेशी विकास, विकास का वितरणात्मक पहलू है। १.४५ अरब जनसंख्या वाले देश में सबसे बड़ी चुनौति यह है कि विकास के लाभों को समाज के सभी वर्गों तथा क्षेत्रों तक कैसे पहुँचाया जाये। देश में समावेशी विकास का मार्ग एक दम सीधा एवं सरल नहीं है अपितु यह अनेक बाधाओं एवं चुनौतियों से भरा हुआ है। समावेशी विकास प्राप्त करने के लिये भारत जैसे देश के सम्मुख निम्नांकित चुनौतियाँ प्रमुख चिन्ता का विषय है:–

- भारत में आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताऐं काफी गहरी हैं। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय की दिशा में लगातार प्रयासों के बाद भी ये असमानताऐं विकास को अवरूद्ध करती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बहुआयामी गरीबी सूचकांक २०२२ के अनुसार भारत में २२८.९ मिलियन गरीब हैं जिसमें देश की १६.४ प्रतिशत जनसंख्या शामिल है तथा जिसमें से ४.२ प्रतिशत जनसंख्या अत्यन्त गरीब है। और लगभग १८.७ प्रतिशत लोग गरीबी के प्रभाव में है।
- क्षेत्रीय असमानता के कारण शहरों में रहने वाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा बेहतर सुविधाऐं प्राप्त हैं, जिसके कारण विकास में असमानताओं को और अधिक बढ़ावा मिलता है। जाति व्यवस्था एवं सम्पदा अन्तराल जैसे कई कारक क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देते है जिसके फलस्वरूप समाज का एक वर्ग दूसरे की अपेक्षा अधिक विशेषाधिकार अर्जित करता है।
- कृषि क्षेत्र में हमारी जनसंख्या के लगभग ४५प्रतिशत लोग जुड़े हुए है लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान काफी कम है, जिसका कारण भूमि जोत का विखण्डन एवं निम्न श्रम उत्पादकता है। जलवायु परिवर्तन, मृदा गुणवत्ता में अभाव एवं पानी में अभाव के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आ रही है।
- निरक्षरता और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत में रोजगार की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों ही निम्न हैं। गुणवत्ता पूर्ण रोजगार अत्यन्त चिन्ता का विषय है क्योंकि ८० प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनोपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। शहरी क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाऐं उपलब्ध हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की भारी कमी है।
- समावेशी विकास के लिये देश के प्रत्येक हिस्से में बुनियादी ढाँचे का विकास आवश्यक है, लेकिन भारत के कई ग्रामीण क्षेत्र अभी भी बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी,बिजली और सड़कों से वंचित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्थाई एवं दीर्घकालीन रोजगार साधनों की आवश्यकता है क्योंकि मनरेगा एव अन्य कई रोजगारपरक योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में किया तो जा रहा है परन्तु उन्हें रोजगार के स्थायी साधनों में शामिल नहीं किया जा सकता है।

समावेशी विकास का मापन

समावेशी विकास को मापने का सबसे अच्छा तरीका है कि देश की प्रगति को उसके सबसे कमजोर एवं निर्धन वर्ग की तरक्की के आधार पर मापना अर्थात देश की जनसंख्या के सबसे कमजोर निचले २० प्रतिशत हिस्से की प्रगति एवं प्रति व्यक्ति आय को मापना।

- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का होना स्वस्थ समावेशी विकास का सूचक है।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9(A)| September 2025

- निरन्तर उच्च होती विकास दर का व्यापक लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचना।

समावेशी विकास हेतु भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदम

समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सार्वजनिक व्यय की भूमिका अत्यन्त आवश्यक है। समावेशी विकास के लिये यह आवश्यक है कि ऊँची वृद्धि दर के साथ आय का प्रभावी तथा वांछित वितरण हो, इसलिये समावेशी विकास हेतु बाजार तथा राज्य की समन्वित भूमिका आवश्यक है। हमारी सरकार सक्रिय रूप से समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम ११वीं पंचवर्षीय योजना में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। इस योजना में समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की बात कही गई। तत्पश्चात १२वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से समावेशी विकास पर केन्द्रित थी तथा इसकी विषय वस्तु 'तीव्र समावेशी एवं सतत विकास' थी। इस योजना मे गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका के अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया।

सरकार द्वारा समावेशी विकास को सुलभ करने के लिये विभिन्न योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं। पं०दीन दयाल अंत्योदय योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, मिड डे मील, मनरेगा, सर्वशिक्षा अभियान आदि योजनाऐं समावेशी विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

वित्तीय समावेशन हेतु सरकार द्वारा कई योजनाओं की शुरूआत की गयी है। इसमें मोबाईल बैंकिंग, प्रधान–मंत्री जन–धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना आदि महत्वपूर्ण योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह योजनाऐं देश के करोड़ो लोगों को बैंकिग सेवाओं से जोड़ने में सफल रही हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप इण्डिया, सर्पोट टू ट्रेनिंग एण्ड एम्प्लायमेन्ट प्रोग्राम फार वीमेन जैसी योजनाओं को प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमिता मंच तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्रयास भी महिलाओं के लिये किये गये वित्तीय समावेशन के प्रयासों में शामिल हैं। ये कार्यक्रम रोजगार सृजन के साथ–साथ नवाचार एवं उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- कृषकों एवं कृषि कार्य हेतु वित्तीय समावेशन के लिये सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- दिव्यांग जनों को समावेशी विकास में सम्मिलित करने के लिये सरकार द्वारा निशक्तता अधिनियम १९९९, सिपडा, सुगम्य भारत अभियान, स्वावलम्बन योजना तथा इसके अतिरिक्त दिव्यांग अधिकार नियम २०१७ जैसी योजनाएं चलाकर बढ़ते हुये आर्थिक विकास को समावेशी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि समावेशी विकास २१वीं सदी की एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह केवल आर्थिक लक्ष्य ही नहीं है अपितु एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। समावेशी विकास की सफलता के लिये एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत में इस हेतु कई प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ सामने हैं जिनका समाधान करने के लिये सरकार, समाज तथा निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें लगातार सुधार एवं नवाचार की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिये समावेशी विकास का महत्व और भी बढ़ जाता है।

सन्दर्भ सूची:–

1. आर्थिक सर्वेक्षण(२०१५) भारत सरकार, नई दिल्ली
2. योजना आयोग(२०११) तेज, सतत और ज्यादा समग्र विकास: १२वींपंचवर्षीय योजना का नजरिया।
3. लाल एस.एन., लाल एस०के०–आर्थिक विकास आयोजन एवं पर्यावरण (२०१०) शिवम पब्लिशिंग हाऊस, इलाहाबाद।
4. सिन्हा वी.सी.एवं सिन्हा रितिका–भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था(२०२४) एस.बी.डी. पब्लिशिंग हाऊस आगरा
5. लाल एस.एन., लाल एस.के.–भारतीय अर्थव्यवस्था: सर्वेक्षण तथा विश्लेषण (२०१४)शिवम पब्लिशर्स, इलाहाबाद।
6. http //yojana.gov.in